socio-economic situation, the broad policy parameters for enhancement of productivity and production in a sustainable manner, and thereby reduction of poverty. Farmers, particularly the small and marginal farmers, will be the focus of attention in the National Policy on Agriculture, both as the mainspring and the beneficiaries of agricultural development.

अकाल के कारण पशुधन की हानि

933. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के कच्छ तथा बनासकांठा में गत कुछेक वर्षो के दौरान सूखे तथा अकाल की स्थिति के कारण कुल कितने पशुओं और अन्य मवेशियों की हानि हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि के संबंध में सरकारी तौर पर कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार को और कितनी सहायता प्रदान की गई है और किस प्रकार से ;और

(घ) क्या सरकार ने उक्त जिलों में पशुधन के बचाव हेतु कोई कारगर उपाए किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि विगत कुछ वर्षो के दौरान इस मामले में इन जिलों से कोई सूचना नहीं मिली हैं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य राहत मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पशुओं की उत्तरजीविका हेतु पर्याप्त चारा प्रदान करने के लिये उपाय किये जाने की सूचना मिली हैं ।

(ग) सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत व पुनर्वास उपाय करना प्रमुखतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं । 1990-91 से आपदा राहत कोष से जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार 3:1 के अनुपात में अंशदान करती हैं,राज्य को वार्षिक रूप से आंबटन किया जाता है । केन्द्रीय अंश चार समान त्रैमासिक किश्तों में वार्षिक तौर पर निर्मुक्त किया जाता है ।

(घ) जी,हां । राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किये जाने की सूचना मिली हैं ।

Assistance of Adivasi Families

934. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps to encourage the farmers of ADIVASI districts of the country, by providing them facilities to promote the agricultural production in their fields; and

(b) if so, the number of such districts benefited in Maharashtra and number of families so benefited during last five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The Government is implementing a number of Central/ Centrally sponsored schemes for the development of agriculature in the country. However, there is no specific separate scheme for Adivasi districts in the country.

(b) Does not arise.

जैव कृषि(आर्गनिक फार्मिग)

935.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जैव कृषि के विभिन्न माध्यमों जैसे-जैव-उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों के जरिए भारत में दूसरी हरित क्रान्ति लाई जा सकती हैं ;

(ख) यदि हां,तो सरकार ने गत पांच वर्षो के दौरान जैव कृषि को बढावा देने हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की है और उसका राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;और

(ग) गत पांच वर्षो के दौरान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर दी गई राजसहायकता का वर्ष-वार एंव मद-वार ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) यह नि:सन्देह रूप से सही है कि कार्बनिक उर्वरकों तथा जैव-कीटनाशकों को दूसरी हरित क्रान्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं । तथापि,गहन उत्पादन पद्वति की उच्च-पोषक तत्व संबंधी मांग की पूर्ति केवल कार्बनिक/जैव उर्वरकों के उपयोग से ही नहीं की जा सकती । इसके लिये पादव पोषक-तत्वों के कार्बनिक

जैविक तथा रासायनिक स्त्रोतों को शामिल करते हुये एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा ।

(ख) समेकित पोषक-तत्व प्रबंध तथा समेकित कीट प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है,जैसे-

(1) जैव उर्वरकों के विकास व उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना ।

(2) उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग ।

(3) समेकित कीट प्रबन्ध ।

इसके अलावा,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दो योजनायें क्रियान्वित कर रहा हैं,नामतः

(1) जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा,

(2) रोगाणु संबंधी अपघटन तथा कार्बनिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना । पिछले पांच वर्षो के दौरान वर्ष-वार तथा योजनावार व्यय का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट** 186,**अनुपत्र सं**. 12]

(ग) पिछले 5 वर्षो के दौरान नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों पर भुगतान की गई रियासत तथा नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता	नियंत्रण रहित उर्वरकों पर राजसहायता
1993-94	4398.97	517.34
1994-95	5241.00	527.95
1995-96	6235.00	500.00
1996-97	5906.08	1674.77
1997-98	7307.00	2596.00

कीटनाशकों/कृमिनाशकों पर कोई भी राजसहायता नहीं दी जा रही हैं ।

Declining price of Oilseeds

936. SHRI C. RAMCHANDRAIAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to news-item in the Economic Times dated the 6th February, 1999 captioned "Oilseeds prices crash, crushers hopes dash";

(b) whether it is a fact that infrastructural bottlenecks and raw material shortage have affected the stability of the oilseed sector;

(c) if so, what are the specific bottlenecks presently affecting this sector;

(d) whether any step is proposed to improve oilseeds availability; and

(e) what steps are proposed to achieve domestic self-reliance in this sector;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes Sir.

(b) and (c) At present, no report of shortage of Oilseeds for crushing by the Oil Mills have been received. On the country, due to non-utilization of available oilseeds production by the oil crushers, the prices of some oilseeds particularly soyabean have fallen. The main reason for less utilisation of oilseeds is the drop in prices of deoiled cake including soyabean deoiled cake in the international market which is acting as a disincentive for oilseeds processors.

(d) and (e) to augment the availability of oilseeds, a Technology Mission on Oilseeds was set up in 1986. The Technology Mission is implementing a Centrally sponsored Oilseeds Production Programme (OPP). Under the scheme, financial assistance is provided for the critical inputs like production and distribution of seed, distribution of seed minikits, sprinkler sets, improved farm implements, gypsum/pyrites, micro-nutrients and rhyzobium culture etc. to the farmers through State Governments. In addition frontline and general demonstrations are